शिक्षकों को कोरोना वारियर्स मानने में है कौन सी दुविधा

शिक्षकों ने कहा शिक्षा में भी निधन पर तत्काल हो स्वत्व का भुगतान

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

प्रदेश में कोरोना ड्यूटी करते हुए लगातार दिवंगत हो रहे शिक्षकों के लिए एक बार फिर कोरोना वरियर्स के साथ साथ फ्रंटलाइन की सुविधा देने की मांग उठी है। आरोप लगाया गया है कि लगातार शिक्षक काम करते हुए दिवंगत हो रहे हैं लेकिन सुविधाओं के नाम पर सरकार फूटी कौड़ी भी नहीं दे रही है। पीड़ा बताई गई कि मध्यप्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना महामारी से शिक्षको की असमय मौत के बावजूद विभाग गंभीर नहीं हुआ है। प्रदेश भर में जिस प्रकार से कोरोना महामारी के बचाव कार्यों में बिना कोई सुरक्षा शिक्षकों को झौंका गया है। उससे शिक्षकों और उनके परिजनों के चेहरो पर चिंता की स्पष्ट लकीरें दिखाई देने लगी हैं। समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिंह पवार ने शासन इस रवैये पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के व्यापक प्रभाव ने हर जिले में शिक्षकों को काल का ग्रास बनाया है। बावजूद इसके शासन द्वारा शिक्षकों को बिना कोई सुरक्षा दिए कोरोना महामारी के बचाव कार्यों में लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

मंत्री की घोषणा के बावजूद नहीं मिल रही राहत

समग्र शिक्षक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी एसएन वर्मा का कहना है कि स्कूल शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद भी मृत शिक्षकों के परिजनों को तात्कालिक आर्थिक सहायता न मिल पाना दुर्भाग्यपूर्ण हैं। समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश संयुक्त सचिव नारायण सिंह हाडा का कहना है कि प्रदेश भर में शिक्षकों को हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन आक्सीजन प्लांट टीकाकरण कार्यक्रम टोल नाको कोरोंटाइन सेंटरों सहित अनेक बचाव कार्यों में लगाया गया है। लेकिन शासन शिक्षकों को कोरोना वारियर्स घोषित करने के मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। जबकि संक्रमित होने के बाद ना तो शिक्षकों को सरकारी खर्च पर इलाज की सुविधा मिल रही है और न ही मृत्यु उपरांत परिजनों को कोई सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

पहले शिक्षकों को कोरोना वरियर्स घोषित करें फिर उनसे काम लें

समग्र शिक्षक संघ प्रदेश सह सचिव देवेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि शासन को जिन शिक्षकों से कोरोना महामारी के बचाव का कार्य लेना है। उन्हें पहले शासन कोरोना वारियर घोषित करें। फिर उनसे कोरोना महामारी के बचाव कार्य में लगाया जाए। इसके साथ ही बीमारी में संबंधित शिक्षक और उनके परिजनों को सरकारी खर्च पर इलाज की सुविधा दी जाए। संगठन के भोपाल जिला अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा का कहना है कि लगातार चारों तरफ से मांग उठने के बाद भी सरकार इस विषय में कोई ठोस कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि विधायकों से लेकर सांसद तक इस मामले में शासन को पत्र लिख चुके हैं।

Badri Gautam

कोरोना योद्धा घोषित न करने से बढ़ती जा रही है कर्मचारियों में नाराजगी

भोपाल (नवदुनिया स्टेट ब्यूरो)। कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में जान जोखिम में डालकर दिन-रात काम कर रहे कर्मचारियों में उन्हें कोरोना योद्धा घोषित न किए जाने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। पंचायत सचिव, रोजगार सहायक आंदोलन पर अड़ गए हैं तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं, संविदा कर्मचारी भी खफा हैं कि अब तक उन्हें कोरोना योद्धा घोषित नहीं किया गया है। सहकारी समितियों के कर्मचारी भी नाराज थे और अनाज खरीद व निशुल्क राशन वितरण का काम बंद करने वाले थे लेकिन सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने उन्हें मना लिया है। उधर, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगे कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग उठाई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में फैले कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास के साथ संविदा और कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी काम कर रहे हैं। सहकारी समितियों के 103 कोरोना

संक्रमित कर्मचारियों का निधन हो चुका है। 28 पंचायत सचिव, सात रोजगार सहायक और कृषि विभाग के 65 से ज्यादा कर्मचारियों का भी निधन हुआ है। अभी तक न तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सचिव और रोजगार सहायकों को कोरोना योद्धा घोषित किया है और न ही ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को योजना में शामिल किया है। संविदा कर्मचारियों को लेकर भी यही स्थिति है। जबकि, पिछले साल राजस्व सहित अन्य विभागों ने अलग-अलग आदेश जारी करके अपने-अपने कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित किया था। पंचायत सचिव संगठन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सचिव और रोजगार सहायक दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। घर-घर सर्वे से लेकर दवा वितरण सहित अन्य कार्य को भी अंजाम दे रहे हैं पर अब तक हमें कोरोना योद्धा घोषित नहीं किया है। इसके बिना शासन की योजना का लाभ दिवंगत सचिव या रोजगार सहायक के स्वजन को नहीं मिलेगा। अब कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इस संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव सहित अन्य अधिकारियों से चर्चा हुई है। वे सचिवों से चर्चा करके निर्णय लेंगे। तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उधर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष मनोहर गिरी ने कहा कि कृषि मंत्री कमल पटेल विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करने के लिए लिख चुके हैं पर अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। उन्होंने तीन दिन में मृतक कर्मचारियों को कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र देने की मांग की है। वहीं, कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कोरोना से जुड़े कामों में लगे सभी कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग की है।

Badri Gautam

मंत्रिपरिषद की बैठक में आज होगा निर्णय

कर्मचारियों की पेंशन योजना में चार फीसद अंशदान बढ़ेगा

भोपाल (नवदुनिया स्टेट ब्यूरो)। वर्ष 2005 के बाद भर्ती हुए अधिकारियों-कर्मचारियों की पेंशन योजना में सरकार अपना अंशदान बढ़ाएगी। राष्ट्रीय पेंशन योजना में अभी सरकार दस फीसद अंशदान देती है। इसे बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 14 फीसद किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इस फैसले से चार लाख से ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

शिवराज सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट से पहले राष्ट्रीय पेंशन योजना में अपना अंशदान चार फीसद बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। अंतिम निर्णय कैबिनेट में होना है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारियों को पहले से 14 फीसद अंशदान का लाभ मिल रहा है। इसे अब राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाएगा। वहीं, वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर खरीदे चमक विहीन गेहूं का वित्तीय भार सरकार उठाएगी। इस पर करीब 30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आ रहा है। दरअसल, केंद्र सरकार एक सीमा तक ही चमक विहीन गेहूं लेती है। यदि इससे अधिक की खरीद होती है तो उसका आर्थिक भार राज्य को ही उठाना पड़ता है। बैठक में इसके अलावा सिनेमा से जुड़े सभी विषयों को वाणिज्यिक कर विभाग से लेकर नगरीय विकास एवं आवास को देने, कृषक मित्र के चयन संबंधी निर्देशों में संशोधन, राज्य व जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के शेष कर्मचारियों के संविलियन के लिए योजना अवधि बढ़ाने, तिलहन संघ के पचामा सीहोर स्थित सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र की मशीनों को साढ़े सात करोड़ रुपये और ग्वालियर में अल्फा नगर कॉलोनी की परिसंपत्ति को 5.87 करोड़ रुपये में सबसे अधिक बोली लगाने वाले निविदाकार को देने के संबंध में विचार किया जाएगा।

प्रस्ताव

- आइएएस, आइपीएस अधिकारियों को 14 फीसद अंशदान मिल रहा
- पिछले साल खरीदे चमक विहीन गेहूं का वित्तीय भार उठाएगी सरकार

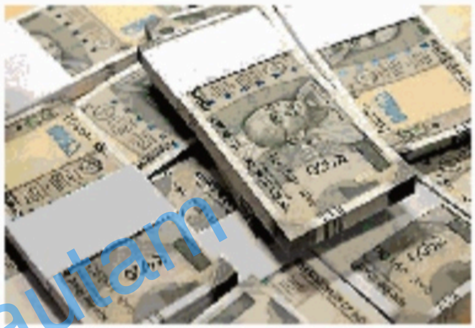

10 फीसद अंशदान देती है अभी सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना में

4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा इस फैसले से

30 करोड़ का वित्तीय भार खरीदे गए चमकविहीन गेहूं पर आएगा

Badri Gautam

नई मार्क्स पॉलिसी के आधार पर रिजल्ट

प्री-बोर्ड न देने वाले 10वीं के दिव्यांग पॉजिटिव फोन पर दे सकेंगे परीक्षा

नई दिल्ली। सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा के लिए असेसमेंट स्कीम के तहत दिव्यांग स्टूडेंट्स को विशेष छूट दी है। इसके मुताबिक दिव्यांग स्टूडेंट्स जो स्कूल लेवल पर हुए असेसमेंट में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनका मूल्यांकन दूसरे जरिए से किया जाएगा। असेसमेंट स्कीम के मुताबिक, अगर कोई दिव्यांग स्टूडेंट्स किसी कारण से सेशन 2020-21 में हुई स्कूल स्तर पर हुई मूल्यांकन योजना जैसे यूनिट टेस्ट, हाफ इयरली टेस्ट या प्री-बोर्ड में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनका असेसमेंट अब पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, क्विज, ओरल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए फोन या किसी और तरीके से सवाल-जवाब कर मार्क्स तय किए जा सकते हैं। स्कूलों से मिले अंकों के आधार पर बोर्ड 20 जून को नतीजे जारी करेगा। बोर्ड ने एक टाइम टेबल भी स्कूलों को भेजा है।

Badri Gautam

जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा हुई स्थगित

भोपाल। जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा अब 15 मई के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं होगी। प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली बॉडी, नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) ने मिजोरम, नागालैंड और मेघालय को छोड़कर देशभर के विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में मई के मध्य में आयोजित किए जाने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय सेलेक्शन टेस्ट 2021 को टाल दिया है।

टेस्ट को स्थगित करने के साथ परीक्षा की नई तारीख की घोषणा नहीं की है। हालांकि, समिति ने स्टूडेंट्स को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिये जाने के उद्देश्य से घोषणा की कि कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा की नई तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व घोषणा की जाएगी।

Badri Gautam

टीचर्स की भर्ती के लिए 31 मई तक कर सकते हैं अप्लाई

सिटी रिपोर्टर | देशभर में सरकारी स्कूल टीचर से लेकर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल तक के हजारों पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए वैकेंसी निकाली है। आवेदन की तारीख पहले 30 अप्रैल थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। एकलव्य मॉडल रेसीडेंशियल स्कूल्स में 17 राज्य में टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया जाएगा। वैकेंसी के लिए वेबसाइट tribal.nic.in या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिक्रूटमेंट (एनटीए) की वेबसाइट recruitment.nta.ac.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

Badri Gautam

आदिम जाति कल्याण विभाग में निचले कर्मचारियों को 14 माह से वेतन नहीं

अधिकारी बोले हमने बजट जारी किया, जिलों में बताया कमी है..

भोपाल(आरएनएन)। महामारी जैसे संक्रमण के दौर में आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन काम करने वाले अल्प वेतनभोगी कर्मचारी आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। कारण भी है कि इन्हें पिछले 14 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। मजेदार यह भी है कि राज्य स्तर से अधिकारी अपनी दलील दे रहे कि बजट जारी कर दिया गया। जबकि जिलों में अधिकारियों का कहना है कि बजट की कमी है। अधिकारियों की इसी लापरवाही में यह सेवक पिछले 1 साल से वेतन के लिए चक्कर काट रहे हैं।

मध्य प्रदेश स्थाई कर्मी कल्याण संघ के प्रांत अध्यक्ष शारदा सिंह परिहार ने आरोप लगाया कि आदिम जाति विकास विभाग सागर में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में स्थाई कर्मियों को 14 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सागर में 5 माह से ज्ञानोदय विद्यालय सागर में 2 माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया। आदिम जाति कल्याण विभाग विकास विभाग सिवनी लखनादौन सतना रीवा पन्ना छतरपुर में स्थाई कर्मियों का पांच 5 माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया है प्रदेश सरकार का नौकरशाह प्रदेश के सबसे पिछड़े निचले वर्ग के कर्मचारी का किस प्रकार शोषण करता है यह एक मिसाल है। एक तरफ मुख्यमंत्री का कहना है की इस महामारी में प्रदेश का कोई गरीब भूखा नहीं मरेगा। दूसरी तरफ प्रदेश के सबसे निचले वर्ग के कर्मचारी का 14 माह से वेतन न मिलना अपने आप में प्रशासन की कार्यशैली को व्यक्त करता है। श्री परिहार ने यह भी बताया की दूरभाष के माध्यम से उपायुक्त रीता सिंह सतपुड़ा भवन भोपाल से बात करने पर उनके द्वारा बताया गया की हेड ऑफिस द्वारा पर्याप्त मात्रा में बजट का आवंटन कर दिया गया है।

अब अगर किसी को वेतन नहीं मिला तो इसमें हेड ऑफिस का क्या दोष है। जिला स्तर की समस्या है। उसमें वे कुछ नहीं कर सकती। प्राचार्य एवं संभागीय उपायुक्त सागर शिव कुमार चौरसिया से फोन से बात की गई तो उनका कहना है कि एससी का मामला है। बजट आवंटन नहीं हुआ है। इसलिए भुगतान नहीं किया गया।

2 साल से समय पर नहीं किया गया है भुगतान

स्थाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश महामंत्री गोविंद तिवारी का कहना है कि इस विभाग के अंतर्गत पिछले 2 साल से कर्मचारियों के समय से भुगतान नहीं हुआ है। उन्होने कहा है कि आदिम जाति कल्याण विकास विभाग मे स्थाई कर्मियो का वेतन भुगतान कभी भी समय से नही किया जाता यह एक विकट समस्या है। इस समस्या के निराकरण के लिए कई बार मुख्यमंत्री से लेकर विभागाध्यक्ष तक पत्राचार किया गया। लेकिन परिणाम ढाक के तीन पात के बराबर निकला। उन्होंने यह भी आरोप लगाया की वेतन भुगतान के लिए जो बजट आवंटित होता है। उसका उपयोग अन्य कार्यों पर कर लिया जाता है। जिसमें कमीशनखोरी या स्वार्थ की पूर्ति होती है।

जन सहयोग से ही रोक सकते हैं कोरोना संक्रमण

भोपाल(आरएनएन)। सीएफआई चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भोपाल की विभिन्न बस्तियों में कोरोना से बचाव के लिए समुदाय के लोगों को निरंतर 2 गज से ज्यादा की दूरी, डबल मास्क लगाने की अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। सभी लोगों विशेषकर 18+ साल से ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन कराने के लिये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है।

सोमवार को आंगनवाड़ी क्रमांक 462, 961 पिपलानी, 40 क्वार्टर में श्री अखिलेश चतुर्वेदी के अगुवाई में तथा सीएफआई के वॉलिंटियर नीता यदुवंशी, ललिता यादव, लीला विश्वकर्मा और आगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सुजाता और श्रीमती लीलावती, सीएफआई के डिप्टी मैनेजर राजेश खत्रा की उपस्थिति में गर्भवती महिलाओं के लिए गोद भराई कार्यक्रम किया गया। जिसमें संस्था द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए दो तरह की दाल मूंगफली दाने, केला, चुकंदर, नारियल हरी सब्जियां, आम, सेव, नींबू इत्यादि चीजों को भेंट दिया गया। साथ ही निरंतर अपनी यूनिटी को बढ़ाने, 2 गज की दूरी के बारे में बताया गया। मास्क वितरण, बार - बार हाथ धोने के लिए प्रेरित किया।

Badri Gautam

बाहर के विद्यार्थी डाक से भेज सकेंगे उत्तरपुस्तिका

कार्यालय प्रतिनिधि। रीवा

हायर एजुकेशन द्वारा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की परीक्षा ओपेन बुक सिस्टम से कराने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में ऐसे विद्यार्थी जो कि प्रदे्रश या फिर दूसरे जिले में रह रहे हैं वे डाक से अपनी उत्तरपुस्तिका मुख्य संग्रहण केन्द्र मॉडल साइंस कॉलेज या फिर महाविद्यालय भेज सकेंगे। लेकिन बाहर से भेजे गए उत्तरपुस्तिका को समय पर मुख्य संग्रहण केन्द्र में पहुंचना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त उत्तरपुस्तिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में हायर एजुकेशन द्वारा एडी कार्यालय को पत्र भेज कर जानकारी दी गई है। साथ ही शीघ्र ही संग्रहण केन्द्र बनाने के बारे में भी कहा गया है।

2020 में भी हुआ था ऐसा

बीते वर्ष भी कोरोना इफेक्ट के कारण भी बाहर रह रहे छात्रों द्वारा डाक से उत्तरपुस्तिका भेजी गई थी। बताया गया है कि अधिकतर परीक्षार्थियों ने जहां मुख्य संग्रहण केन्द्र मॉडल साइंस कॉलेज में उत्तरपुस्तिका भेजी थी वहीं कुछ परीक्षार्थियों ने अपने महाविद्यालय में उत्तरपुस्तिका भेजी थी। महाविद्यालयों द्वारा मुख्य संग्रहण केन्द्र में उत्तरपुस्तिका भेजी गई। हालांकि बीते वर्ष ऐसा भी देखने को आया था कि संग्रहण केन्द्रों द्वारा निर्धारित समायावधि के बाद भी उत्तरपुस्तिका मुख्य संग्रहण केन्द्र भेजी गई थी।

वेबसाइट में अपलोड होंगे प्रश्न • अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी दिनों में विश्वविद्यालय तय तिथि में सभी विषयों क्वेश्चन पेपर वेबसाइट में अपलोड किए जाएंगे। वेबसाइट से छात्र क्वेश्चन पेपर अपलोड कर उत्तरपुस्तिका में उत्तर लिखेंगे।

अगस्त तक रिजल्ट घोषित करना होगा चुनौती

हायर एजुकेशन द्वारा फाइनल ईयर की परीक्षा जून माह में और अन्य सेमेस्टर/वर्ष की परीक्षा जुलाई माह में आयोजित करने का निर्देश दिया है। कोरोना इफेक्ट और विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में कर्मचारियों की 10 प्रतिशत उपस्थिति के बीच ऐसा कर पाना फिलहाल संभव नजर नहीं आ रहा है।

16 पेज और 250 शब्दों में उत्तर • परीक्षार्थी जिस उत्तरपुस्तिका में उत्तर लिखेंगे वह 16 पेज का होगा। एक प्रश्न का उत्तर कम से कम 250 शब्दों में लिखना होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को उत्तरपुस्तिका के प्रथम पेज का प्रारूप सभी कालमों को भर कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करना होगा।

Badri Gautam

एंकर स्टोरी

वीडियो कांफ्रेंसिंग में विभागीय मंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन

पंचायत सचिव व रोजगार सहायकों की हड़ताल शुरू, कोरोना योद्धा के स्पष्ट आदेश निकलने के बाद स्थगित होगा आंदोलन

शहर प्रतिनिधि, भोपाल । पंचायत सचिव व रोजगार सहायकों की सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई। हड़ताल के दौरान दोनों संगठनों के पदाधिकारियों की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा हुई। जिसमें मंत्री ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर सकारात्मक आश्वासन दिया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश जारी नहीं होते, हड़ताल जारी रहेगी।

मप्र पंचायत सचिव संगठन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा व सहायक सचिव संगठन के अध्यक्ष रोशन सिंह परमार ने बताया कि विभाग द्वारा 26 अप्रैल को जिला कलेक्टरों को पंचायत सचिव/सहायक सचिव समेत ग्रामीण विकास विभाग के अमले को जिला वार कोरोना योद्धा के अंतर्गत पात्र कर्मी के आदेश जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। बावजूद इसके प्रदेश भर से 10-12 कलेक्टर द्वारा पूर्व में जारी आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार आदेश निरस्त करने के लिए भोपाल स्तर से वीसी में निर्देश दिए गए हैं। कोरोना महामारी के बीच डयूटी करते हुए मध्यप्रदेश में 50 से अधिक सचिव एवं सहायक सचिवों की मृत्यु हो चुकी है। बावजूद इसके अधिकारियों के द्वारा प्रदेश के 46 हजार सचिवों एवं सहायक सचिवों को कोरोना योद्धा के नाम पर आंख मिचौली की जा रही है। सुबह से शाम तक बिना सक्षम अधिकारी के लिखित ड्यूटी आदेश जारी किए। वाट्सएप मैसेज के माध्यम से काम कराया जा रहा है। प्रदेश भर के बड़े अधिकारी एसी रूम में अपने परिवार के साथ घर में आराम से बैठकर सचिवों एवं सहायक सचिवो को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं और कोरोना योद्धा के नाम पर भी षडयंत्र कर रहे है। इसी के चलते कार्यालय बंद करके काम बंद का निर्णय लिया है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि मंत्री से चर्चा के साथ सकारात्मक आश्वासन मिला है। लेकिन जब तक स्पष्ट रूप से आदेश जारी नहीं होते, आंदोलन जारी रहेगा।

बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने किया काम का बहिष्कार, अब मंत्री से मिलने के बाद शुरू होगा आंदोलन

एक सप्ताह के अंदर मांगा मिलने का समय, मांगे नहीं मानने पर शुरू होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल

शहर प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी समेत प्रदेश भर में बिजली विभाग के करीब 42 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों ने सोमवार को काम का बहिष्कार किया। कर्मचारी कार्य स्थल पर पहुंचे, लेकिन कोई काम नहीं किया। हालांकि कर्मचारियो ने स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधा में कार्यरत कर्मचारियों को बहिष्कार से अलग रखा था। बाह्य बिजली कर्मचारी संघ के शिव राजपूत ने बताया कि विगत वर्ष कोरोना की प्रथम लहर में ऊर्जा विभाग से प्रदेश के बिजली अधिकारी व कर्मचारियों (नियमित, संविदा व आउटसोर्स) को फ्रंटलाइन वर्कर मानकर कोरोना योद्धा योजना में शामिल किया गया था। परंतु इस वर्ष कोरोना वायरस की अधिक घातक लहर के बावजूद बिजली कर्मचारियों को फ्रंट लाइन से साइड लाइन करते हुए कोरोना योद्धा घोषित नहीं किए जाने से कर्मचारियों में भय, आक्रोश व निराशा का माहौल है। प्रदेश की 6 बिजली कंपनियों में लगभग 55 हजार से अधिक अधिकारी/ कर्मचारी (नियमित, संविदा व आउटसोर्स) कार्यरत है। विगत दो माह से कोरोना से संक्रमित होकर 200 से अधिक बिजली अधिकारी/ कर्मचारियों की अकाल मृत्यु हो चुकी है तथा 3000 से अधिक संक्रमित होकर जीवन और मृत्यु के बीच इलाज के लिए अस्पतालों, ऑक्सीजन, रेमडीसीवीर की तलाश में दर-दर भटक कर जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खेद का विषय है कि बिजली कंपनियों के स्वयं के अस्पताल/ औषधालय तथा डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ होने के बाद भी प्रबंधन ने यूनियनों की मांग के बावजूद भी इन अस्पताल/ औषधालयों में अपने कर्मचारियों व उनके परिजनों के कोविड के इलाज के इंतजाम नहीं किये हैं। वहीं रेलवे विभाग ने रेल के कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर अनुकरणीय पहल की है। राजपूत ने बताया कि सोमवार को प्रदेश भर में कर्मचारियों ने एक दिनी कार्य का बहिष्कार किया। अब एक सप्ताह के अंदर विभागीय मंत्री प्रद्युम्न तोमर से मिलने का समय मांगा है। मंत्री के साथ बैठक में समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, तो एक सप्ताह बाद पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन काम का बहिष्कार किया जाएगा। मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री बीडी गौतम का कहना है कि बिजली कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग की जा रही है। गौतम ने बताया कि विरोध स्वरूप आउटसोर्स कर्मचारियों का आंदोलन शुरू हो गया है। सभी कर्मचारी संगठन उनके साथ है।

Badri Gautam

रिटायरमेंट के दिन ही मिलेंगे कर्मचारियों को पेंशन के सभी फायदे

नई दिल्ली, एजेंसी

सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। सरकार ने सेवानिवृत्ति पर मिलने वाला सभी तरह के पेंशन लाभ को बिना देरी किए समय पर देने किया फैसला लिया है। कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग ने सभी मंत्रालयों को पेंशन का लाभ सेवानिवृत्ति के दिन ही सुनिश्चित करने के लिए कहा है। दरअसल, विभाग ने पाया है कि नियमों और निर्देशों में निर्धारित सम्यसीमा और भविष्य सॉफ्टवेयर (ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली) के माध्यम से प्रक्रियाओं का सरल और सुव्यवस्थित करने के बावजूद पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) और सेवानिवृत्ति लाभ देरी से देनी के बहुत सारे मामले प्रकाश में आए हैं। विभाग के

पास बड़ी संख्या में मिली शिकायतें में सेवानिवृत्ति के कई महीनों बाद भी सेवानिवृत्ति देय राशि का भुगतान न करने से संबंधित हैं। सेवानिवृत्ति की बकाया राशि के निपटान में देरी से मुकदमेबाजी भी होती है। अधिकांश मामले में कोर्ट ने देरी की अवधि में ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया और विभाग के अधिकारियों को लेकर तल्ख टिप्पणी भी किया है।

नियमित रूप से निगरानी करने का निर्देश

सेवानिवृत्ति का लाभ देने में देरी न हो इसके लिए सरकार ने सभी विभाग के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह खुद से पेंशन के मामले की निगरानी करें। इसके साथ यह भी सहमति बनी है कि पेंशन मामलों की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक कार्यालय/ विभाग में एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा। इसमें %भविष्य सॉफ्टवेयर% से उपलब्ध जानकारी का उपयोग किया जाएगा। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के अवसर पर कार्यालयों में अक्सर विदाई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह सबसे उपयुक्त समय है, जिसका उपयोग पेंशन मामलों की प्रगति की समीक्षा करने और संबंधित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति देय राशि के समय पर भुगतान के महत्व के बारे में किया जा सकता है। प्रत्येक विदाई समारोह में उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख, उस विभाग के सभी कर्मचारियों के पेंशन मामलों की प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं, जो अगले छह महीनों में सेवानिवृत्ति होने वाले हैं।

विभाग को देनी होगी जानकारी

अगर किसी विभाग को पेंशन प्रक्रिया में देरी का मामला मिलता है तो उसे आगे इसकी जानकारी देनी होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक विभाग द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के सचिव को एक अर्धवार्षिक विवरण देने को कहा जा सकता है उन मामलों को लेकर जिनमें सेवानिवृत्ति के दो महीने से अधिक होने के बावजूद पीपीओ जारी नहीं किया गया है। इसमें यह भी पूछा जाएगा कि पीपीओ जारी करने में क्यों देरी हुई। अगर विभाग की गलती पाई गई तो कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार की तैयारी यह सुनिश्चित करना है कि सेवानिवृत्त के दिन उस कर्मचारी को सभी रिटायरमेंट लाभ का भुगतान कर दिया जाए।सरकारी कर्मचारी को समय पर पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए पेंशन नियम 1972 में एक समयसीमा निर्धारित की गई है। समयसीमा के अनुसार, सेवा के सत्यापन और अन्य तैयारियों की प्रक्रिया एक साल पहले शुरू करनी है। वहीं, सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से छह महीने पहले फॉर्म जमा करना, जबकि कार्यालय प्रमुख को चार महीने पहले पीएओ के पास पेंशन का मामला भेजना जरूरी है। वहीं, पीएओ को पीपीओ जारी कर सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले सीपीएओ को भेजना चाहिए।

Badri Gautam

वैक्सीनेशन सेंटर पर पदस्थ शिक्षक के साथ की मारपीट

बीएससी नर्सिंग कॉलेज का मामला, शिक्षक संघ ने खोला मोर्चा

भास्कर संवाददाता | उज्जैन

वैक्सीनेशन सेंटर पर पदस्थ एक शिक्षक ने ड्यूटी के दौरान एक व्यक्ति पर मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने कलेक्टर आशीष सिंह को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है।

बीएससी नर्सिंग कॉलेज में पदस्थ संदीप बौरासी ने कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा वे कॉलेज में वॉरियर का कार्य कर रहे थे। सोमवार दोपहर 2.30 बजे राजेश बोड़ाना आए और बिना वेरिफिकेशन के डॉ. केसी परमार से फोन पर बात कराकर 18 प्लस वाले में वैक्सीनेशन कराना चाह रहे थे लेकिन बिना वेरिफिकेशन फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा था। इस कारण रुकने का कहा। इस पर बोड़ाना ने मुक्का मारा और साथ आए अन्य सदस्य ने भी मारपीट की। सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन करवाया जा सकता है। उन्होंने कलेक्टर से सुरक्षा देने का आग्रह किया है।

आरोपी को गिरफ्तार करें

प्रांतीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. कैलाश बारोड़ और राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मनोहर गिरी ने कलेक्टर और एसपी से आरोपी को गिरफ्तार करने का आग्रह किया। मंगलवार को प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर व एसपी से मुलाकात करेगा।

Badri Gautam

वैक्सीनेशन में तैनात शिक्षिका को ब्रेन हेमरेज, इलाज नहीं मिल रहा

माधवनगर में भर्ती, इलाज के लिए दूसरे अस्पताल लेने को तैयार नहीं

भास्कर संवाददाता | उज्जैन

वैक्सीनेशन टीम में तैनात शिक्षिका नजमा को ब्रेन हेमरेज हो गया। वह पांच दिन से कोरोना अस्पताल माधवनगर में भर्ती है। उसे न तो इलाज मिल पा रहा है और न कोई अन्य अस्पताल भर्ती करने को तैयार है।

नलिया बाखल स्थित कन्या मावि की शिक्षिका नजमा पति रमजान की छत्रीचौक डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ी। पति रमजान खान के अनुसार डॉ. सोनाली अग्रवाल का इलाज कराया। कोरोना कोरोना टेस्ट भी कराया। दो दिन बाद उनके सिर में तेज दर्द हुआ। कोरोना की शंका के चलते माधवनगर अस्पताल में भर्ती किया। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आ गई। डॉक्टरों ने बताया ब्रेन हेमरेज है। कोरोना अस्पताल होने से हमें अंदर जाने की मनाही है। गुरुवार से वह बेड पर बेसुध है। कोरोना नहीं है, इसलिए कोरोना का इलाज नहीं हो रहा, ब्रेन हेमरेज है, इसके लिए अन्य अस्पताल में इलाज की जरूरत है। रमजान बताते हैं कि शहर और इंदौर तक के अस्पतालों में संपर्क कर चुके लेकिन कोई भर्ती करने को तैयार नहीं है। भास्कर ने कोरोना के नोडल अधिकारी डॉ. एचपी सोनानिया से संपर्क की कई बार कोशिश की लेकिन उन्होंने मोबाइल रिसीव नहीं किया और एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज देखने के बाद भी जवाब देना उचित नहीं समझा।

Badri Gautam

नेशनल पोर्टल की रिपोर्ट में खुलासा- प्रदेश में छह साल से कम उम्र की 64 प्रतिशत बालिकाएं ही जा रही हैं स्कूल

बच्चियों को पढ़ाने में मध्यप्रदेश देश में 25वें नंबर पर

इंदौर/ग्वालियर | DBStar

लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन बच्चियों की शिक्षा के मामले में मप्र की स्थिति बेहतर नहीं है। यहां साल से कम उम्र की 64 प्रतिशत बच्चियां ही स्कूल जा रही हैं। सभी राज्यों की बात करें तो इस मामले में देश में मप्र का नंबर 25वां है। यह चौंकाने और चिंता में डालने वाला तथ्य नेशनल पोर्टल की रिपोर्ट में सामने आया है। डीबी स्टार ने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया तो पता चला कि इस मामले में सबसे बेहतर स्थिति केरल की है। जहां 95.4 फीसदी बच्चियां स्कूल जाती हैं। सबसे खराब स्थिति राजस्थान की है। जहां सिर्फ 54 फीसदी बच्चियां ही स्कूल गई हैं।

नंबर 1 केरल से सीखें हम... वहां 95.4 फीसदी बच्चियां जाती हैं स्कूल

राज्य	बालिकाएं	राज्य	बालिकाएं	राज्य	बालिकाएं
केरल	95.4	हिमाचल प्रदेश	79	ओडिशा	67.8
मिजोरम	91.2	महाराष्ट्र	77.4	छत्तीसगढ़	67.6
गोवा	85	तमिलनाडु	77.2	अरुणाचल प्रदेश	67.1
अंडमान निकोबार	84.7	पंजाब	76	जम्मू कश्मीर	65.6
मेघालय	83	असम	75	मध्य प्रदेश	64
त्रिपुर	81.9	पश्चिम बंगाल	74	उत्तर प्रदेश	63
मणिपुर	81.7	उत्तराखंड	72.7	तेलंगाना	62.2
दिल्ली	81.7	गुजरात	72	आंध्र प्रदेश	62
नागालैंड	81	कर्नाटक	70.7	झारखंड	61.1
सिक्किम	79.7	हरियाणा	70.3	राजस्थान	57.2

किसी भी राज्य में लक्ष्य 100% पूरा नहीं

केंद्र सरकार द्वारा बच्चों को शिक्षा देने के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। साथ ही करोड़ों रुपये खर्च भी किये जाते हैं। वहीं, सभी राज्यों को 100 फीसदी तक शिक्षण व्यवस्था करने का लक्ष्य दिया गया है। लेकिन देशभर में एक भी राज्य इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया है।

राष्ट्रीय औसत से भी पांच फीसदी पीछे

रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 6 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों को शिक्षा देने के मामले में जहां देश की राष्ट्रीय औसत 68.8 फीसदी है। जबकि मध्यप्रदेश की औसत इस मामले में 64 फीसदी है। यानि हमारा प्रदेश राष्ट्रीय औसत से भी लगभग पांच फीसदी पीछे चल रहा है। जबकि यहां तमाम योजनाओं का संचालन करने का दावा किया जाता है।

Badri Gautam

देश के 90 से अधिक काउंसलर्स **CBSE दोस्त फॉर लाइफ** पर देंगे स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब

पहली बार 9वीं से 12 वीं तक के स्टूडेंट्स की ऐप के जरिए होगी कॅरियर काउंसलिंग

प्रीति जैन • IamBhopal
Mobile no. 9827080406

पिछले 23 सालों से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) प्री और पोस्ट हेल्पाइन के जरिए देशभर में बोर्ड परीक्षा दे रहे स्टूडेंट्स की मदद करता था। लेकिन इस साल पहली बार सीबीएसई नए रूप में स्टूडेंट्स के सामने साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन व कॅरियर काउंसिलिंग की फैसिलिटी लेकर आया है। इस पर देशभर के 90 से अधिक काउंसलर्स स्टूडेंट्स को उनकी कॅरियर संबंधी जिज्ञासाओं के जवाब देंगे। सीबीएसई के दोस्त फॉर लाइफ (CBSE Dost For Life App) ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके स्टूडेंट्स लाइव चैट कर सकते हैं।

फ्री ऑफ कॉस्ट चुन सकते हैं अपना स्लॉट

इस काउंसिलिंग फैसिलिटी के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। स्टूडेंट्स व पैरेंट्स हफ्ते में तीन बार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को अपनी पसंद का स्लॉट चुन सकते हैं। पहले स्लॉट का समय सुबह 9.30 बजे से 1.30 बजे तक व दूसरा स्लॉट दोपहर 1.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक रहेगा।

पैरेंट्स और टीचर्स के लिए भी सुविधा

12 वीं पास करने वाले स्टूडेंट्स के पास इस समय कॅरियर काउंसिलिंग के अवसर कम हैं, क्योंकि न तो वे अपने टीचर्स से मिल पा रहे हैं, न ही काउंसिलिंग के लिए कहीं संपर्क कर पा रहे हैं।

12 वीं के बाद उनके पास कॅरियर के क्या-क्या विकल्प होंगे वे कहां-कहां एडमिशन ले सकते हैं, आदि जानकारियां काउंसलर्स से सीधे संपर्क करके ले सकते हैं। वहीं 10 वीं के स्टूडेंट्स सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर सुझाव ले सकते हैं। इसके अलावा यह सुविधा 9 वीं व 11 वीं के स्टूडेंट्स, पैरेंट्स व टीचर्स के लिए भी है।

ऑडियो-वीडियो मैसेजेस भी होंगे

इस काउंसलिंग ऐप के जरिए स्टूडेंट्स को परीक्षा से होने तनाव को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए काउंसलिंग सेशन को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं एक्सपर्ट एडवाइस भी दी जाएगी। स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ फिट रखने के लिए भी टिप्स दिए जाएंगे, जिसमें परीक्षा की चिंता, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, अवसाद जैसी समस्याओं के समाधान की कोशिश की गई है। इसका उद्देश्य छात्रों के मनोवैज्ञानिक-सामाजिक कल्याण में सुधार करना है। इसके अलावा इस काउंसलिंग ऐप में ऑडियो-विजुअल मैसेज भी जारी किया है।

इस बार अलग तरह के हो सकते हैं सवाल

"स्टूडेंट्स अपने सवाल भेजेंगे और वे सवाल देश के किसी भी काउंसलर को अपने ऐप पर मिलेंगे। स्टूडेंट्स के हर तरह के सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सालों से सीबीएसई के लिए वॉलेंटरी काउंसिलिंग कर रहा हूं। ज्यादातर स्टूडेंट्स के सवाल क्या होंगे इसके हिसाब से प्लानिंग की है, लेकिन इस बार सवाल अलग हो सकते हैं।

– **डॉ. राजेश शर्मा**
काउंसलर, सीबीएसई

मानसिक रूप से राहत देने की कोशिश

"यह सुविधा 10 मई से शुरू हो गई है। अब स्टूडेंट्स इस ऐप पर अपने सवाल चैटबॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स ही नहीं टीचर्स व पैरेंट्स भी बात कर सकते हैं। इस समय स्टूडेंट्स परेशानी का सामना कर रहे हैं तो कोशिश होगी कि उन्हें मानसिक रूप से राहत पहुंचाते हुए उनके सभी सवालों के जवाब देंगे।

–**मीना शर्मा**, काउंसलर, सीबीएसई

Badri Gautam

यूजी फाइनल और पीजी चौथे सेमेस्टर की परीक्षा जून में

जबलपुर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते आगे बढ़ाई गई यूजी फाइनल और पीजी चौथे सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी। विभाग ने विश्वविद्यालयों को जून में परीक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए है। सागर विश्वविद्यालय जल्दी इन परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर सकती है। अधिकारियों के मुताबिक परीक्षाएं जून दूसरे व तीसरे सप्ताह में करवाई जाएगी। विद्यार्थियों को पांच दिन के भीतर प्रश्नों के जवाब लिखकर कॉपियां जमा करना होगी। फिलहाल विश्वविद्यालय अगले सप्ताह आनलाइन बैठक कर सकता है।

अप्रैल में होने वाली ऑफलाइन परीक्षाएं संक्रमण की वजह से स्थगित हो गई है। अब बीए, बीकॉम, बीएससी फाइनल ईयर, एमए, एमकॉम और एमएससी चौथे सेमेस्टर की ओपन बुक पद्धति से परीक्षा होगी। विभाग ने जून में परीक्षा और जुलाइ में रिजल्ट देने पर जोर दिया है। ताकि अगस्त से कॉलेजों में आनलाइन प्रवेश शुरू किए जा सके। विभाग के मुताबिक यूजी फर्स्ट-सेकंड ईयर व पीजी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई में करवाने के निर्देश दिए है। विभाग ने मुख्य परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित करने का कहा है। आदेश विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ने जारी किया है। विभाग की तरफ से दिशा-निर्देश मिलने के बाद विश्वविद्यालय परीक्षा की तैयारियां शुरू कर सकता है।

55 हजार विद्यार्थी होंगे शामिल

यूजी फाइनल और पीजी चौथे सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले करीब 55 हजार विद्यार्थी है। इनकी परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय ने पेपर तैयार कर लिए है। पेपर अपलोड करने की तारीख तय होना बाकी है। यह निर्णय आनलाइन बैठक में लिया जा सकता है। बताया जाता है कि विद्यार्थियों को उत्तरपुस्तिका अपने कॉलेजों में जमा करना होगी। वहां से कॉपियां मूल्यांकन केंद्र आएगी। फिर केंद्र को कॉपियां जांचने का काम करना होगा।

Badri Gautam

कोरोना : इग्नू ने स्थगित की जून टर्म की परीक्षाएं

नई दिल्ली । इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने कोरोना संकट के कारण जून टर्म की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। ये परीक्षाएं 15 जून से शुरू होनी थीं। अब कोरोना संकट के बाद विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षाओं की नई तिथि घोषित की जाएगी। साथ ही इग्नू ने जून टर्म के असाइनमेंट जमा करने और जनवरी सत्र में दाखिले के लिए पुन: पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 31 तक मई कर दी है। पहले यह तिथि 30 अप्रैल तक थी। (ब्यूरो)

Badri Gautam

भोज विवि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वेबिनार आज

भोपाल। मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्व विद्यालय में मंगलवार को दोपहर 12.15 बजे से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया है। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी प्रो. अजय खरे होंगे। सेमिनार की अध्यक्षता विवि के कुलपति प्रो. जयंत सोनवलकर करेंगे। कुलसचिव डा. एलएस सोलंकी शामिल होंगे। (नप्र)

Badri Gautam

अंतिम वर्ष छोड़ विश्वविद्यालयों के छात्र बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट

नई दिल्ली (ब्यूरो)। कोरोना संक्रमण से मचे हाहाकार के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा फैसला विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया है। वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाएं कराने या फिर छात्रों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। हालांकि अब तक जो स्थिति है, उसमें ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को बगैर परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विश्वविद्यालयों ने यूजीसी की ओर से पिछले साल परीक्षाओं को लेकर तय की गई गाइडलाइन को आधार बनाया है।

यूजीसी के सचिव डा. रजनीश जैन के मुताबिक विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान होते हैं। ऐसे में उन्हें परीक्षाओं और शैक्षणिक सत्र आदि को लेकर अपने स्तर पर कोई भी फैसला लेने का पूरा अधिकार है। यूजीसी का कहना है कि कोरोना संक्रमण का प्रभाव देश के अलग-अलग हिस्सों में कम और ज्यादा है। ऐसे में परीक्षाओं को लेकर इस बार कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन अभी नहीं बनाई गई है। इस बीच, विश्वविद्यालयों ने स्नातक के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को आंतरिक आकलन या फिर पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान करके प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है।

'दोस्त फार लाइफ एप' लांच

रांची (ब्यूरो)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड(सीबीएसई) ने विद्यार्थियों के लिए 'दोस्त फार लाइफ एप' लांच किया है। सोमवार से इस एप से कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए परामर्श कार्य शुरू किया गया है। छात्र व अभिभावक सुविधानुसार समय का चयन कर सकते हैं। काउंसिलिंग एप में सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहार संबंधी शैक्षिक सामग्री भी है। एप से परीक्षा की चिंता, इंटरनेट एडिक्शन डिसआर्डर, अवसाद के समाधान की कोशिश की गई है।

Badri Gautam

प्रदेश के 315 कॉलेजों की लाइब्रेरी और लैब होगी अपग्रेड, विभाग ने प्राचार्यों से मंगाए प्रस्ताव

उचित स्थान पर सील सिक्का और हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र करना होगा प्रस्तुत

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

प्रदेश के 315 कॉलेजों की लाइब्रेरी व लैब को अब उच्च शिक्षा विभाग अपग्रेड करेगा। इसको लेकर विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और जरूरत वाले कॉलेजों से प्रस्ताव मंगाए हैं। प्राचार्य को आवेदन करते समय इस बात का ख्याल रखना होगा कि विश्व बैंक परियोजना या रुसा के तहत जारी की सूची में शामिल नहीं किया गया हो। इसके लिए उन्हें उचित स्थान पर सील सिक्का और हस्ताक्षर लगाकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

बढ़ाई तारीख, 15 तक कर सकेंगे आवेदन

विभाग द्वारा इसके लिए पहले छह मई तक कॉलेजों से प्रस्ताव मंगाए गए थे, लेकिन वह कोरोना कर्फ्यू के कारण प्रस्ताव नहीं भेज पाए हैं। नतीजन अब विभाग ने कोरोना कर्फ्यू के चलते तारीख बढ़ा दी गई है। लैब को अपग्रेड करने और ई-लाईब्रेरी बनाने के लिए कालेज प्राचार्य अब 15 मई तक आवेदन कर पाएंगे।

निर्धारित तिथि के बाद आवेदन निरस्त

निर्धारित तिथि बीतने के बाद विभाग पहुंचे आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। विभाग ने प्राचार्यों को आदेशित किया है कि उन्हें विगत तीन वर्षों में लैब और ई-लाईब्रेरी के कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। इसके संबंध में ई-मेल कर सूचित करना होगा।

कई कॉलेजों में लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी और लैब की समुचित व्यवस्था नहीं

दरअसल, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश भर में 515 पारंपरिक कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इनमें से 200 कॉलेज विश्वबैंक व रूसा से मिलने वाले अनुदान के लिए चयनित किए गए हैं। इन्हें साल भर विभिन्न मदों से ग्रांट दिया जाता है, लेकिन 315 कॉलेजों को केवल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मिलने वाले ग्रांट का ही सहारा है। इसके चलते कई कॉलेजों में लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी और लैब की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसी कमी को दूर करने के लिए विभाग ने जरूरत वाले कॉलेजों से प्रस्ताव मंगाए हैं।

हिंदी विवि की बैठक स्थगित

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की सोमवार को आयोजित होने वाली साधारण परिषद की ऑनलाइन बैठक को स्थगित कर दिया गया है। इस बैठक में परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बैठक में होना पहले ही कैंसिल था, लेकिन उपाध्यक्ष उच्च शिक्षामंत्री मोहन यादव भी व्यस्तताओं के चलते बैठक में शामिल नहीं हो सके। अब बैठक की नई तारीख अलग से जारी की जाएगी। बता दें कि हिंदी विवि की साधारण परिषद की बैठक सोमवार को प्रस्तावित की गई थी। इसको लेकर कुलपति व अन्य सदस्य निर्धारित समय पर ऑनलाइन कनेक्ट हो गए थे। लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने ऐनवक्त पर बैठक में शामिल होने से असमर्थता जताई। इसके कारण कुलपति प्रो. रामदेव भारद्वाज ने बैठक को स्थगित कर एक पत्र मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री को भेजा है। अब मुख्यमंत्री या मंत्री जब समय देंगे तब परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कुलपति के कार्यकाल की वृद्धि और झोलाछाप डाक्टरों के लिए चलाए जा रहे डिप्लोमा कोर्स को परिषद की सहमति के लिए रखा जाना था। इन दोनों मुद्दों सहित करीब सात बिंदुओं के एजेंडे पर अपनी सहमति मिलना थी।

Badri Gautam

उमंग हेल्पलाइन पर किशोर रोजाना कर रहे 250 से 300 कॉल

मैडम, रात-दिन एक ही चिंता है कहीं घर वालों को कोरोना न हो जाए, इस कारण नहीं आती नींद

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

मेरे पिता कोरोना पॉजिटिव आए हैं मैं उनको कैसे समझाऊं, आज ही उनकी रिपोर्ट आई है, और वह घर पर ही आइसोलेशन में हैं, वह बात नहीं कर रहे हैं और कमरे में बंद हैं। कुछ इसी प्रकार के चिंता से भरे फोन इन दिनों उमंग हेल्पलाइन नंबर 14425 पर पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।

कोविड-19 से बचाव को लेकर लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू के बाद हेल्पलाइन पर किशोर-किशोर के कॉल्स संख्या में इजाफा हुआ है। किशोर-किशोरियों के अलावा अन्य लोग भी इस हेल्पलाइन कॉल कर रहे हैं। इन कॉल्स से यह बात सामने आई है कि प्रदेश में बच्चे कोरोना संक्रमण और अपने कॅरियर को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्हें अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों के सुरक्षा के साथ ही अपने कॅरियर की भी चिंता सताने लगी है। हालांकि उमंग हेल्पलाइन पर कॉल करने वाले किशोर-किशोरियों की समस्याओं का समाधान काउंसलर लगातार कर रहे हैं।

कोरोना कर्फ्यू में किशोर-किशोरी कंफ्यूज, सता रही अपनों की चिंता, कॅरियर और एग्जाम को लेकर हो रहे परेशान

खास बातें

- कोरोना कर्फ्यू के बाद हेल्पलाइन पर कॉल्स संख्या में इजाफा हुआ
- किशोर-किशोरियों के अलावा अन्य लोग भी कर रहे कॉल्स

हेल्पलाइन पर कॉल की स्थिति

- 13 जनवरी 2020 से लेकर 9 मई 2021 तक 1 लाख 79 हजार 97 से कॉल आए हैं।
- जनवरी 2021 से लेकर 30 अप्रेल तक 42 हजार 321 कॉल आए हैं।
- सिर्फ अप्रेल 2021 में ही 2307 कॉल कोरोना से संबंधित हैं।
- हेल्पलाइन पर आने वाले कॉल्स में 70 फीसदी कोविड-19 और 30 फीसदी एग्जाम व करियर से संबंधित होते हैं।
- रोजाना करीब 250 से 300 कॉल हेल्पलाइन पर पहुंच रहे हैं।

हेल्पलाइन पर इस प्रकार के भी आ रहे कॉल, जवाब दे रहे काउंसलर

किशोर : मैं अकेले रहकर शहर में पढ़ाई कर रहा हू, कोविड-19 के बारे में कोई भी नई जानकारी जैसे ही मिलती है, मनघबराता है, और अलग-अलग निगेटिव विचार आते हैं इनके बारे में सोचना कैसे बंद करूं?
काउंसलर : वाट्सप पर उड़ी सभी जानकारियां सत्य हो आवश्यक नहीं अतः किसी भी नई जानकारी के मिलने पर वैधता को जांच लें इससे आपके मन में भ्रामक और नकारात्मक विचार नहीं आएंगे परिजनों व रिश्तेदारों से फोन पर कॉल या वीडियो कॉल द्वारा बात करें इससे आपका अकेलेपन खत्म होगा।
किशोर : पिछले 6 दिनों से कोविड-19 और अभी शरीर में घबराहट महसूस हो रही हू उसी को लेकर परामर्श लेना चाहता हूं।
काउंसलर : कुछ सरल प्राणायाम और श्वसन क्रियाओं को करके घबराहट को कम किया जा सकता है तथा धैर्यपूर्वक अपने असुरक्षा के भावों का सामना करना होगा, खाली समय में अपनी रुचियों को बढ़ावा दें, एक सकारात्मकता विकसित की जा सकती है। कोशिश करें कि कोविड-19 से हटकर कुछ और बात करें। हालांकि 24*7 कवरेज देखने से आप परेशान हो सकते हैं और आपके प्रियजनों को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है।
किशोर : इस महामारी में सबको बहुत परेशानी हो रही है मुझे बहुत डर लगता है और मैं बहुत परेशान रहता हू लगता है कि कहीं मेरे परिजनों को भी कोरोना ना हो जाए।
काउंसलर : कोरोना के सुरक्षा के नियमों का पालन किया जाए, तो हम सुरक्षित बने रह सकते हैं। अपने परिवार को भी इस बारे में सहजता से प्रशिक्षित करें एवं डरे नहीं। भय से उत्पन्न होने वाला मानसिक तनाव हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। आप उनके साथ अन्य तरीकों से वीडियो कॉल, ई-मेल टेलीफोन और टेक्सटिंग से जोड़ सकते हैं और बेहतर महसूस कर सकते हैं।
किशोर : बीमार होने की चिंता की वजह से मुझे नींद नहीं आती है क्या करूं?
काउंसलर : आप टीवी, न्यूज, अखबार तथा मोबाइल पर कोविड-19 से जुड़ी नकारात्मक खबरों को नजर अंदाज करें। वॉट्सएप पर आ रहीं भ्रांतियों से दूरी बनाएं तथा भ्रामक बातों पर ध्यान न दें। इस विषय में कम से कम बात करें। अपने दोस्तों परिचितों से बातचीत करते समय उनका हाल-चाल लें, जिससे उनकी हो रही चिंता न हो, संतुलित आहार समय पर लें, नींद पर्याप्त लें। घबराहट होने पर गहरी लंबी सांसें लेने का अभ्यास करें, कोविड-19 संक्रमित अन्य व्यक्तियों से अपनी तुलना न करें। हर व्यक्ति की अलग-अलग रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है।
महिला : मेरे पति हॉस्पिटल में एडमिट है और मुझे उनको लेकर नकारात्मक ख्याल आते हैं, क्या करूं?
काउंसलर : सबसे पहले महिला को सामान्य अवस्था में लाने के लिए एक जगह आराम पूर्वक बैठने तथा पानी पीने के लिए कहा। महिला की सभी बातों को धैर्य पूर्वक सुना और उसके मन में आ रहे नकारात्मक विचारों पर बात की। इसके सकारात्मक पक्ष जैसे उसके पति को सभी चिकित्सकीय सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, दवाइयां समय परदी जा रही हैं, इन पहलुओं पर बात की, साथ ही जो नकारात्मक विचार या खो देने का भय है, अनिश्चित और भविष्य की बारे में सोचने का किस प्रकार आपकी वर्तमान पर प्रभाव पड़ रहा है, इन पहलुओं पर बात की।

बच्चों के साथ अभिभावकों से भी की बात

कोरोना संक्रमण और कॅरियर को लेकर बच्चे बेहद कंफ्यूजन में है। ऐसे में आने वाले कॉल्स में अभिभावकों, शिक्षकों से भी बातचीत की जा रही है। बच्चों के साथ रहने और समय देने की सलाह दी। काउंसलर समय-समय पर बच्चों का फॉलोअप भी ले रहे है। किशोर-किशोरी निःसंकोच होकर हेल्पलाइन नंबर 14425 पर कॉल करें।

माया बोहरा, डायरेक्टर उमंग हेल्पलाइन

Badri Gautam

बीयू... यूजी की परीक्षा जून और पीजी की जुलाई से

2.75 लाख छात्र 325 कॉलेजों में जमा कर सकेंगे आंसरशीट

ओपन बुक पैटर्न परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू

एजुकेशन रिपोर्टर | भोपाल

बरकतउल्ला विवि की स्नातक स्तर (यूजी) की परीक्षाएं जून और स्नातकोत्तर (पीजी) की परीक्षाएं जुलाई से शुरू होंगी। दोनों परीक्षाओं में करीब पौने तीन लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे। इस बार भी पिछले साल की तरह कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से परीक्षा ओपन बुक पैटर्न पर होगी। इस बार 325 कॉलेजों में परीक्षा की कॉपी जमा हो सकेंगी। बीयू के कुलसचिव डॉ. एचएस त्रिपाठी ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के बाद परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछली बार ओपन बुक पैटर्न परीक्षा में हुई गफलत के मद्देनजर बीयू परीक्षा की कॉपी जमा करने के लिए संकायवार अलग-अलग व्यवस्था करेगा। कॉपी प्राइवेट कॉलेजों में भी परीक्षा कॉपी जमा की जा सकेंगी। लीड कॉलेजों को इसकी जिम्मेदारी देंगे। कॉपी जमा करने के लिए 325 से ज्यादा केंद्र बनाए जाएंगे।

अब 20 मई तक छात्र जमा कर सकेंगे परीक्षा आवेदन

बीयू ने वार्षिक मुख्य परीक्षा पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी होमसाइंस, बीए मैनेजमेंट, बीबीए, बीसीए, बीकॉम ऑनर्स के छात्रों के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन जमा करने की तारीख अब 20 मई कर दी है।

Badri Gautam

विश्वविद्यालय में इस साल भी नहीं बढ़ेंगी सीटें

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों में इस साल कोई सीट बढ़ने की संभावना नहीं है। फिर भी अंतिम फैसला विभागाध्यक्षों की राय के बाद लिया जाएगा। कोरोना के चलते विवि प्रशासन सीटें बढ़ाने से बच रहा है। प्रवेश प्रक्रिया को लेकर अगले महीने कुलपति डा. रेणु जैन बैठक बुलाएंगी जिसमें फीस, प्रवेश नियम और सीट वृद्धि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।

कोविड गाइडलाइन के मुताबिक प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों के बीच छह फीट की दूरी रखनी है। इस लिहाज से एक कक्षा में 25-30 विद्यार्थियों के बैठने की ही क्षमता है। ज्यादातर विभागों में पर्याप्त क्लास रूम नहीं हैं। इसी कारण पिछले सत्र में भी सीटें नहीं बढ़ाई गई थीं। इस बार कोरोना की दूसरी लहर में ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसके चलते विवि भी

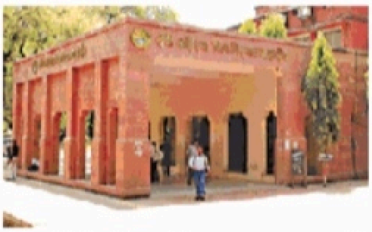

विभागों में भीड़ नहीं बढ़ाना चाहता। इसे लेकर सीटों में वृद्धि करना मुश्किल नजर आ रहा है। वैसे विभागाध्यक्षों की राय के बाद ही विवि प्रशासन किसी नतीजे पर पहुंचेगा। वैसे कुछ विभागों ने सीट नहीं बढ़ाने को लेकर कुलपति से बातचीत की है। अधिकारियों के मुताबिक, संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा की जाएगी। प्रवेश समिति से भी फीस और सीटों पर चर्चा होगी। कुलपति का कहना है कि जून में प्रवेश संबंधित मुद्दों पर विभागाध्यक्षों से बातचीत करेंगे। कार्यपरिषद सदस्यों के सामने भी प्रस्ताव रखेंगे। उसके बाद ही गाइडलाइन बनाएंगे।

कोरोनाकाल : कक्षाएं बंद, अब माहेश्वरी कालेज के शिक्षक मदद के लिए मैदान में

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोनाकाल में जब पढ़ाई और कक्षाएं बंद हैं, माहेश्वरी कालेज के शिक्षक भी मदद के लिए मैदान में उतर गए हैं। आरपीएल माहेश्वरी कालेज, छत्रीबाग के शिक्षकों ने कोरोना मरीजों के स्वजन और कोरोना कर्फ्यू में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों की सेवा का अभियान शुरू किया है। सोमवार से कालेज के शिक्षक शहर के सरकारी अस्पतालों तक पहुंचे। अस्पतालों के बाहर तपती धूप में परेशान हो रहे मरीजों के स्वजनों की भूख-प्यास मिटाने की जिम्मेदारी निभाई।

प्राचार्य डा.राजीव कुमार झालानी के साथ अलग-अलग गाड़ियों में शिक्षकों के दल बोतलबंद पानी और नाश्ते के साथ सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल, एमआरटीबी अस्पताल और एमवायएच पहुंचे। अस्पताल के बाहर मरीजों के स्वजन को पानी और नाश्ता उपलब्ध कराया। सड़कों पर ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों को भी ठंडे पानी की बोतलें दी। शिक्षक प्रो.खुशी वर्मा, डा.संजीव जटाले, डा.मनीष जैन, प्रो.अंजू वर्मा, प्रो.चेतन जोशी, प्रो.जयेश नानकानी, अंजुबाला पंवार, पूर्णिमा भाटी, संजीव गोंडले, प्रमोद देवड़ा, सोहन चौहान, जीवन यादव समेत कालेज की टीम अलग-अलग अस्पतालों और सड़कों पर पहुंचकर हर दिन सेवा करेगी।

Badri Gautam

अच्छे भविष्य के लिए विद्यार्थी चाहते हैं कि परीक्षा हो लेकिन स्थिति सुधरने के बाद

12वीं की परीक्षा को लेकर स्कूल, विद्यार्थी और माता- पिता है असमंजस में

जबलपुर (नईदुनिया रिपोर्टर)। 10वीं कक्षा की परीक्षाओं के निर्णय के वाद अव सभी को इंतजार है कि 12वीं की परीक्षा के लिए क्या निर्णय लिया जाएगा। सीवीएसई वोर्ड द्वारा एक जून को अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि क्या होना है। वहीं स्कूलों, विद्यार्थियों के साथ ही माता-पिता को भी निर्णय का इंतजार है। सभी की राय की वात है तो इसके लिए मिलीजुली प्रक्रिया है। साथ ही यह भी है कि जो वच्चे मेरिट होल्डर हैं वो क्या चाहते हैं और जो सामान्य वच्चे हैं वो क्या चाहते है। इसके अलावा कुछ वच्चों ने भविष्य में जिस क्षेत्र में करियर वनाने के सपने देखे हैं उसके लिए 12वीं की परीक्षा के परिणाम कितने जरूरी हैं? इस बात पर भी उनके विचार निर्भर करते हैं।

कोविड से वचाव वड़ी चुनौती: स्कूल प्रशासन हो या माता-पिता और विद्यार्थी। सवके सामने वड़ी चुनौती ही कोविड के संक्रमण से वचाव। कपिला शर्मा की वेटी को 12वीं की परीक्षा देना है और अभी हाल ही में पूरा परिवार कोविड संक्रमण का सामना कर चुका है। ऐसे में कपिला नहीं चाहतीं हैं कि परीक्षा हो। उनका कहना है कि एक साल हो जाएगा चलेगा पर इन हालात में सुरक्षा जरूरी है। वच्चे कितना वचा पाएंगे खुद को संक्रमण से।

स्कूलों को भी है निर्णय का इंतजार: स्मॉल वंडर्स स्कूल की प्राचार्य संगीता ग्रोवर ने वताया कि सभी को इंतजार है कि एक जून को क्या निर्णय होता है। जो भी होगा मानना होगा। वोर्ड को वैसे सारी स्थितियां पता हैं हो। हो सकता है अभी परीक्षाएं न हों लेकिन आगे ली जाएं। वच्चों को तैयारी तो रखना ही है।

रॉयल स्कूल की प्राचार्य वर्षा चौहान ने वताया कि वच्चों और माता-पिता के मन में डर तो है ही। जो स्वाभाविक भी है। वीमारी भी ऐसी है। साथ ही वच्चे भी पढ़- पढ़ कर थक गए हैं। आनलाइन पढ़ाई ने उनकी लिखने, ज्यादा देर वैठने की आवत को भी छुड़ा दिया है। ऐसे में परेशानी तो वनी हुई है।

12वीं के परिणामों पर पूरा कॅरियर निर्भर करता है ऐसे में कोई भी निर्णय लेने के पहले कई वातों को गंभीरता से सोचना जरूरी होगा। कई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनका होना ही 12वीं के परिणामों पर आधारित है।

विद्यार्थियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

रैनिशा शर्मा।

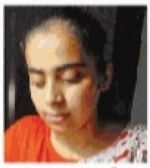

निष्ठा गोल्हानी।

12वीं कक्षा में मैथ्स- कॉमर्स लेकर पढ़ने वाली निष्ठा गोल्हानी ने वताया कि वो चाहती है कि 12वीं की परीक्षा न हो, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा होना चाहिए। 10वीं की ही तरह 12वीं के लिए भी कुछ निर्णय होना चाहिए। वहीं मैथ्स-कॉमर्स लेकर पढ़ने वाले अद्विक यादव ने वताया कि उन्हें डीयू में दाखिला चाहिए, जो कि विना 12वीं के वेहतर परिणाम के संभव नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि परीक्षा हो लेकिन जुलाई- अगस्त में, अभी नहीं। एक अन्य 12वीं की विद्यार्थी रैनिशा शर्मा ने वताया कि उनके घर में सभी को कोरोना हुआ है। ऐसे में अभी परीक्षा होना तो उनके लिए परेशानी है। पर परीक्षा का होना भी जरूरी है। क्योंकि विना इसके कैसे पता चलेगा कि किसे क्या आता है?, यह तो परीक्षा से ही तय होगा। आगे भी जव परीक्षा हो तो पूरी सुरक्षा के साथ ही होना चाहिए। यदि आप अभी वोलेंगे तो माता-पिता अभी तो परीक्षा देने नहीं जाने देंगे।

Badri Gautam

शिक्षिकाओं ने बढ़ाया हौसला

सतना | व्यंकट क्रमांक-1 विद्यालय में मदर्स डे के उपलक्ष्य में रविवार को ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में विद्यालय की शिक्षिकाओं ने एक नवाचार करते हुए उन बच्चों को खोज निकाला जिनकी माताएं अब इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसे बच्चों को वेबिनार के जरिए उत्साहवर्धन किया गया और शिक्षिकाओं ने बच्चों को भरोसा दिलाया कि जरूरत की घड़ी में शिक्षिकाएं उनके साथ खड़ी रहेंगी और ये लोग ही उन बच्चों की माताएं हैं। इस दौरान स्नेहल चौरसिया, हर्ष मिश्रा, संकल्प मिश्रा, महेंद्र मिश्रा, रोहित कुमार विश्वकर्मा एवं शिवांगी अहिरवार ने विचारों को साझा किए।

Badri Gautam

9वीं-12वीं के लिए 'दोस्त फॉर लाइफ एप' लॉन्च

हफ्ते में तीन दिन एप से काउंसलिंग ले सकेंगे छात्र

अजमेर | कोरोना के कारण स्थगित या रद्द हुई परीक्षाओं के कारण सीबीएसई ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सोमवार को 'दोस्त फॉर लाइफ' एप लॉन्च किया है। यह ऑनलाइन लर्निंग एप होगा, जिसका इस्तेमाल सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्र और उनके अभिभावक कर सकेंगे। एक्सपर्ट सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को काउंसलिंग करेंगे। विद्यार्थी व अभिभावक सुबह 9:30 से 1:30 या दोपहर 1:30 से 5:30 तक दोनों में से किसी स्लॉट को चुन सकेंगे।

Badri Gautam

जारी होने लगे 9वीं, 11वीं के परिणाम

कई विद्यालयों ने विमर्श पोर्टल में अपलोड किया डाटा

जागरण, रीवा। कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों का परिणाम अब आगामी 15 मई को घोषित होना है। इस लिहाज से विद्यालय प्रबंधनों द्वारा छात्रों का परिणाम तैयार करने कार्यवाही की जा रही है। इसमें से जिले के कई सरकारी विद्यालयों ने कक्षा 9वीं, 11वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। ऐसे विद्यालयों ने कक्षावार परिणाम लोक शिक्षण संचालनालय के विमर्श पोर्टल पर परिणाम अपलोड भी कर दिया है। अब जिन विद्यालयों के परिणाम नहीं आये हैं, उनके परिणाम विमर्श पोर्टल पर अपलोड होना शेष है।

बता दें कि विद्यालयों को छात्रों की मासिक परीक्षा व अर्द्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर विद्यालयों को परिणाम तैयार करना है, जिसके लिए विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा कसरत की जा रही है। हालांकि लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के डर की वजह से विद्यालयों को परिणाम तैयार करने में परेशानी हो रही है। फिर भी उम्मीद की जा रही है कि लोक शिक्षण द्वारा निर्धारित समय 15 मई तक सभी विद्यालयों के छात्रों के परिणाम जारी हो जायेंगे।

कोरोना के चलते बढ़ाया था समय

गौरतलब है कि इसके पहले लोक शिक्षण संचालनालय ने गत 30 अप्रैल को परिणाम घोषित करने के आदेश दिये थे परंतु कोरोनाकाल के चलते ऐसा नहीं हो सका। तभी लोक शिक्षण ने परिणाम घोषित करने विद्यालयों को 15 दिन का समय और दे दिया। बता दें कि इस साल भी होम और बोर्ड परीक्षा पर कोरोना का असर पड़ा। लिहाजा कक्षा 9वीं और 11वीं की मुख्य परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। फिर आयुक्त लोक शिक्षण ने संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, डीईओ व विद्यालय प्राचार्यों को निर्देशित किया कि उक्त कक्षाओं के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाये, जिसके लिए परिणाम जारी करने की विधि भी बताई गई। अब उक्त विधि के तहत ही परिणाम घोषित किये जाने लगे हैं। बहरहाल, परिणाम की जानकारी को विमर्श पोर्टल पर अपलोड करने की समय सीमा 20 मई तय की गई है। यानि विद्यालय प्रबंधनों को थोड़ी और राहत देने का प्रयास संचालनालय ने किया है।

Badri Gautam

स्कूल के दोस्तों से मिलने को बेचैन बच्चे

घर में नहीं मिल रहा स्कूल जैसा माहौल, कई दफा टीचर और दोस्तों से बच्चों को करानी पड़ती है फोन से बात

सिटी रिपोर्टर . सतना

लॉकडाउन में सुकून देने वाली घर की चारदीवारी अब झुंझलाहट देने लगी है। क्या बड़े क्या बच्चे सभी बाहर निकलने को छटपटा रहे हैं। ऐसे में बच्चे और उनके पैरेंट्स की चुनौतियां काफी बढ़ गईं हैं। बच्चों के लिए स्कूल और उनके दोस्त उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं लेकिन कोरोना ने सबसे दूर कर रखा है। जिससे बच्चे उन दिनों को यादकर भावुक हो जाते हैं और दोस्तों से मिलने की जिद करने लगते हैं। पैरेंट्स का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है।

बोरियत है सबसे बड़ी समस्या

अभिभावकों का कहना है कि आज के समय की सबसे बड़ी समस्या घर में हो रही बोरियत है। जिन्हें पैरेंट्स भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि बच्चे घर पर योग कर रहे हैं, कुकिंग और घर का काम कर रहे हैं। घर में टीवी देख रहे हैं लेकिन वे बोर हो जाते हैं। ऐसे ही एक पैरेंट्स अरुण त्रिपाठी का कहना है कि मेरा बेटा शिवम कक्षा 3 में है वह स्कूल को इतना मिस करता है कि खाना-पीना ठीक से नहीं करता है। घर में एक ही रूटीन बना हुआ है घर में टीवी, टैब, फोन बस यही है।

याद आ रहे टीचर

स्वाती जो की 4 क्लास में है वह पैरेंट्स हमेशा टीचर से मिलने के लिए उत्सुक रहती है। वह घर में कई बार टीचर को याद करती रहती है इसलिए उनके पैरेंट्स मनोज और शिखा उनकी बात उनकी टीचर से करा देते हैं और उनसे उन्हें कुछ नया करने की सलाह भी दिलवाते हैं ताकि वे घर में अच्छे से रहे।

कैसे दूर की जाए बच्चों की उदासी

यह मानकर चलें कि लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर ही देखने को मिल रहा है और ये स्वाभाविक है क्योंकि आपके बच्चे जो दिन भर एक्टिव रहते थे उनकी दुनिया बस घर में सिमट कर रह गई है। मनोरोग चिकित्सक डां. राजीव गुप्ता के मुताबिक इस समय में हम डिजिटल मीडिया का सबसे ज्यादा प्रयोग करें। आप अपने बच्चे को भी इसका बेहतर इस्तेमाल करना सिखाएं। वीडियो कॉल के जरिए अपने बच्चे को उनके दोस्तों या अन्य पारिवारिक सदस्यों से बातचीत कराएं। परिस्थितियों के बारे में अच्छे से जानकारी दें। उनको बताएं कि इस समय में सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके दोस्त भी अपने घर में ही रह रहे हैं। बच्चे बोर ना हो इसका खास ख्याल रखें। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनके कमरे में ढेर सारा खिलौना रख दें। आप अपने बच्चे के संग बेहतर संवाद स्थापित करते रहें क्योंकि बच्चे बेहद संवेदनशील होते हैं।

● फिलहाल तो बच्चे को दोस्तों और टीचर से वीडियो कॉल करके खुश हो जाते हैं। प्रयास करते हैं कि घर पर उनका मन लगा रहे।
- अंजली झा

● बच्चों के मनोरंजन का भी खास ध्यान रखते हैं।बच्चे के साथ बैठकर ऑनलाइन गेम खेलते हैं। ऑनलाइन पार्टी का आयोजन भी करते हैं।
- मोनिका यादव

● हमें अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। बाहर खेलने भी नहीं जा पाते हैं ऐसे में बोरियत होती है। दोस्तों हर रोज फोन पर बात करते हैं।
- अथर्व त्रिपाठी

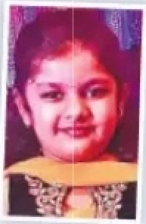

● बोरियत को दूर करने के लिए पढ़ाई के साथ मां के कामों में हेल्प करते हैं और पेंटिंग, डांस को घर में सीखते हैं जिससे मनोरंजन हो जाता है।
- आरवी चतुर्वेदी

Badri Gautam

शिक्षकों का संलग्नीकरण विभाग के लिए बना चुनौती

रीवा| सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर हाई स्कूल व हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की काफी कमी बनी हुई है। इसके बावजूद बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो विषयवार होने के बावजूद जिला अथवा ब्लॉक कार्यालयों में पदस्थ होकर अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं और स्कूलों में संबंधित विषय के शिक्षकों के अभाव में पठन-पाठन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसके बावजूद उच्च अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी का भरपूर फायदा संबंधित विषयवार शिक्षक उठा रहे हैं। खासकर गणित, विज्ञान और शिक्षकों की कमी काफी खल रही है फिर भी देखा जा रहा है कि ऐसे शिक्षक सीएसी, बीएसी से लेकर अन्य वरिष्ठ पदों पर आसीन हैं। अधिकारी बनकर अपने ही समकक्ष शिक्षकों पर धौंस जमाने से नहीं चूकते। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षकों की समस्या कोई आज की नहीं है। कई वर्ष से यह समस्या स्कूलों में बनी हुई है। इन विषयों के शिक्षकों की काफी कमी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई बार उच्च स्तर से ऐसे शिक्षकों के रिडिप्लायमेंट संलग्नीकरण, अटैचमेंट आदि पर रोक लगाई जा चुकी है लेकिन ऐसे निर्देशों का कभी पालन सही ढंग से नहीं किया गया। आज भी तमाम स्कूली छात्र-छात्राएं इसका खामियाजा भुगत रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शासन स्तर से ऐसे शिक्षकों के रिडिप्लायमेंट समाप्त करने के पीछे मंशा यह है कि स्कूलों में अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।

Badri Gautam

सरकारी महाविद्यालयों से सम्बद्धता शुल्क के लिए मांगे प्रस्ताव

उच्च शिक्षा विभाग ने एक सप्ताह का दिया समय, निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन भेजनी होगी जानकारी

जागरण, रीवा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को एक करोड़ से अधिक सम्बद्धता शुल्क सरकारी व गैर सरकारी महाविद्यालयों से नहीं मिली है। अधिकांशतः सरकारी महाविद्यालयों की सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय को अप्राप्त है। ऐसे सरकारी महाविद्यालयों से उच्च शिक्षा विभाग ने अब प्रस्ताव मांग लिया है। सत्र 2021-22 की जिन महाविद्यालयों को सम्बद्धता शुल्क राशि विभाग से नहीं मिली है, उन महाविद्यालय को एक सप्ताह में प्रस्ताव विभागीय पोर्टल में ऑनलाइन भेजना होगा। इस बाबत विभाग ने एक प्रारूप भी जारी किया है। साथ ही विभाग ने स्पष्ट उल्लेखित किया है कि केवल नियमित पाठ्यक्रमों की शुल्क अदायगी विभाग द्वारा की जायेगी। महाविद्यालय में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रम की सम्बद्धता शुल्क राशि का बंदोबस्त महाविद्यालयों को अपने स्तर पर करना होगा।

गौरतलब है कि विश्वविद्यालय प्रशासन से रीवा व शहडोल सम्भाग के तकरीबन 71 सरकारी महाविद्यालय सम्बद्ध हैं। जिनसे विश्वविद्यालय को हर साल सम्बद्धता नवीनीकरण शुल्क लेनी होती है। कोर्सवार ली जाने वाली उक्त सम्बद्धता शुल्क लगभग कई सरकारी महाविद्यालयों ने पिछले एक साल से विश्वविद्यालय को अदा नहीं की है। इतना ही नहीं, कुछ सरकारी महाविद्यालयों की तो और अधिक समय से सम्बद्धता शुल्क बकाया है। जिससे विश्वविद्यालय को आर्थिक नुकसान हो रहा है लेकिन आपस में उलझे विश्वविद्यालय के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

Badri Gautam